Shri Jha, I want to make an announcement. This morning the Minister of State for Finance has given some information to the house about the bank robbery in Calcutta. He has received further information which he would like to place on the Table of the House for the information of the members. So, with the permission of the House, I would ask him to place it on the Table of the House.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : इसमें प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि इतना तो हमको बता दें कि इतनी बड़ी जो डकैती हुई है उसको करने वाले वास्तव में डकैत ही हैं या कोई विदेशी एजेन्ट तो नहीं हैं जो कि डकती के नाम पर यह कर रहे हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : उन आदमियों के ऐंटिसिडेन्ट्स क्या हैं, वे कौन आदमी हैं? पोलिटिकल हैं या प्रोफेशनल डक्वैट्स हैं? और वे अकेले बंगाल में ही हैं या सारे देश में फैले हुए हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly listen to me. The Minister can give only such information which he has received from the State Government.

SHRI M. N. REDDY: (Nizamabad): Let him read it. We are all anxious to hear him. It is a short statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have no objection, if Shri Jha agrees. It is a short statement.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): Let him lay it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, to save the time of the House, let it be laid on the Table. You will get copies of this.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): I lay a copy of the statement on the Table of the House.

Statement

In continuation of the statement made this morning regarding the robbery in the Russel Street branch of the State Bank of India on the 12th December 1969, certain further particulars have since been received from the Chief Secretary to the Government of West Bengal.

According to the State Government's report a gang of 10 or 12 armed persons arrived at the branch of the State Bank of India in three vehicles including a lorry and a station wagon. Some of these persons entered at the bank premises while others remained out-side. Those who entered the bank premises opened fire at random fatally injuring one of the guards of the bank. They took away four boxes containing cash in notes and small coins to the tune of Rs. 4,62,218.65 and other securities worth more than Rs. 6 lakhs. While this operation was being conducted inside the bank premises, the remaining members of the gang outside exploded hand grenades and opened fire from their guns to scare away passerby. Thereafter, the entire gang escaped in the vehicles in which they had come under cover of gun fire. The entire operation lasted about five minutes. The lorry and the station wagon in which the dacoits came were later found abandoned at two places near the bank and two bundles of notes amounting to about Rs. 20,000 in all and some securities were recovred. One person has been arrested in connection with the dacoity and several other persons are being interrogated. The investigation of the case which has been taken up by the detective department of the Calcutta Police is proceedings.

18.39 Hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

STRUCTURAL CHANGES IN MANAGEMENT OF WORLD BANKS

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने 17 नवम्बर को मेरे प्रश्न संख्या 16 का जो उत्तर दिया था उसी के ऊपर मैं यह बहस उठा रहा हूं। मैं ने अपने प्रश्न में कहा था कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स विद दी इंटरनेशनल मानेटरी फंड, जिसको दूसरे शब्दों में पेपर गोल्ड भी कहते हैं, उसमें इंक्रीज होने से हिन्दुस्तान या जो

[श्री शिव चन्द्र झा]

दूसरे मुल्क हैं वे कुछ ज्यादा ड्रा करने के लिए एन्टाइटिल्ड हो जाते हैं ताकि उनकी जो फारेन एक्सचेंज की डिफीकल्टीज हैं वे दूर हो सकें। असल में यह जो इन्टरनेशनल मानेटरी फंड हैं या फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक हैं उसका ज्यादा फायदा विकासशील देशों को होना चाहिए। लेकिन हकीकत में जिस रूप में उसकी बनावट है—इन्टरनेशनल मानेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की, उसके मातहत तो जो राष्ट्र आलरेडी विकसित हैं उन्हीं को ज्यादा फायदा जाता है बनिस्बत उन राष्ट्रों के जोकि डेवलपिंग हैं। मन्त्री महोदय ने जवाब में कहा था कि जनवरी, 1970 से जो स्पेशल ड्राइंग राइट लागू होगा तीन सालों के लिए उसमें 9·5 मिलियन के एलोकेशन का फैसला हुआ है। उसका एक चौथाई यानी 2·60 मिलियन, जो एशियाई अफ्रीकी और दूसरे डेवलपिंग नेशन्स हैं वह उसके एन्टाइटिल्ड होंगे लेकिन तीन चौथाई का फायादा डेवलपिंग नेशन्स को चला जायेगा। लेकिन मन्त्री महोदय ने साफ नहीं किया कि मौजूदा बनावट में किस तरह से यह फायदा उनको चला जाता है और विकासशील देशों को क्या करना चाहिए जिससे कि विकासशील देशों की हकीकत में जो फायदा मिलना चाहिए वह उनको मिल सके।

कब्ल इसके कि उसके सन्दर्भ में मैं सवाल करूं मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक और इन्टरनेशनल मानेटरी फंड जो है वह मोटे तौर पर अमरीकी फाइनेन्स कैपिटल का एक हथकंडा है। देखने में तो यह आता है कि हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देशों को डेवलेप्मेंट के कामों के लिए कर्जा मिलता है लेकिन हकीकत में यह उनका एक हथकंडा है कि जो उनका सरप्लस फाइनेन्स कैपिटल है उसको अनडेवलप्ड नेशन्स में इन्वेस्ट कर दें। इसमें भी प्राफिट बनाने की ही बात है। यह बात साफ हो जायेगी कि अगर उहम उसकी बनावट पर हिस्टारिकली थोड़ा सा गौर करें। पिछले युद्ध में जो एलाइड नेशन्स, थीं, ब्रिटेन और अमेरिका, उन्होंने इस पर विचार शुरू किया कि लड़ाई के बाद बर्बादी हो जायेगी और फारेन एक्सचेंज की डिफीकल्टी आयेगी तो उसको कैसे हल किया जाये। एलाइड नेशन्स में रूस भी था लेकिन इसमें उसका हाथ नहीं था। यही दो मुल्क थे जिन्होंने सोचा कि लड़ाई के बाद करेन्सी स्टैबिलिटी के लिए इन्टरनेशनल मानेटरी फंड कायम करें और इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए इन्टरनेशनल बैंक फार रिकांस्ट्रक्शन ऐंड डिवलप्मेंट का विकास, यूरोप में जो बर्बादी हुई उसको मद्दे नजर रखते हुए किस तरह से करें। सन् 44 की स्प्रिंग में बैठक हुई। यू० एस० ए० यू० के० के रिप्रेज़ेंन्टेटिव्ज़ और यू० एन० मानेटरी ऐंड फाइनेंशियल कांफ्रेन्स एटलांटिक सिटी में बुलाई गई—उसमें 44 नेशन्स थे। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स में बैठक हुई 44 देशों की, हिन्दुस्तान भी उसमें था। उस वक्त यहां पर अंग्रेज़ थे और उनकी तरफ से श्री सी० डी० देशमुख रिप्रेजेन्टेटिव थे। पहली जुलाई, 1944 को बैठक हुई। रूस उसमें नहीं था। तीन हफ्ते के बाद जा करके उसका ड्राफ्ट बना। उसके हिसाब से इन्टरनेशनल मानेटरी फंड और इन्टरनेशनल बैंक फार रिकांस्ट्रक्शन ऐन्ड डिवेलपमेन्ट —ये आर्टिक्लस तैयार किए गए। यह सब 27 दिसम्बर, 1945 में हुआ और सन् 1946 में वर्ल्ड बैंक का दफ्तर खोला गया। रूस उसमें नहीं था बाद में क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड भी इसमें से हट गए। अभी 31 दिसम्बर, 1968 को इसमें 110 मेम्बर थे। उसमें 11,800 मिलियन रुपया 85 नेशन्स को दिया है। यह बात तो वर्ल्ड बैंक की है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में भी दो आस्पेक्ट्स हैं। एक इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन है। यह कारपोरेशन जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज्यादातर दृष्टि में रखकर, इसका मकसद प्राइवेट इन्टरप्राइजेज़ से है :

"It grew out of the realisation in the early 1950 that there were gaps in the

international financial structure in regard to private enterprise and private investment which the World Bank could not fill."

अब आप देखिए कि एक तो वर्ल्ड बैंक की शुरूआत हुई अमरीकन कैपिटल का आउटलेट बनाने के लिए लेकिन उससे भी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो फिर इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन की शुरूआत होती है। वह बना जुलाई, 1956 में। दिसम्बर, 1968 तक इसके 90 मेम्बर रहे हैं और 289 मिलियन डालर 39 देशों की प्राइवेट कम्पनीज़ में इन्वेस्ट किया गया।

उसके बाद इसका एक तीसरा विंग भी आ गया है—इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन। यह इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन एक कंफ्यूजिंग एसोसिएशन है। इसमें लुभाने के लिए दस साल का ग्रेस दे कर के कुछ कम रेट पर देते हैं। जब मुल्क आजाद होने लगे तो उनको खासकर जरूरत थी । दिखाने के लिए तो रेट चीप होता है लेकिन वह असलीयत नहीं है। एग्रिकलचर पर वह जयादा जोर देता है। एग्रिकलचर पर ज्यादा जोर देने का मतलब यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आप जानते ही हैं कि मोटे तौर पर अफ्रीका और एशिया में एग्रिकलचर प्राइवेट सेक्टर में है। देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एग्रिकलचर के विकास के लिए यह किया जा रहा है लेकिन एशिया और अफ्रीका में पब्लिक सेक्टर की लहर है, उसको दबाने का यह एक काम हो रहा है। इस चीज़ को कांउटरएक्ट करने की यह एक बड़ी साजिश है। प्राइवेट सेक्टर में एग्रिकलचर को बढ़ावा देने के लिए एक वातावरण सा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

अब आप इंटरनेशनल डिवेलेपमेंट एसोसिएशन को लें। यह सितम्बर, 1960 में बना। तब इसके पन्द्रह मेम्बर थे। 31 दिसम्बर, 1968 में इसके 102 मेम्बर थे। इसने 45 राष्ट्रों को 1960 मिलियन डालर का क्रेडिट दिया।

एक तीसरी आर्गेनाइज़ेशन है इंटरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन। यह तथा इंटरनेशनल डिवेलेपमेंट एसोसिएशन, दोनों की मोटे तौर पर यू० एन० के अंग हैं, उससे सम्बद्ध हैं। एफ० ए० ओ०, आई० एल० ओ०, आदि सब मोटे तौर पर यू० एन० की बाडीज़ हैं। सवाल बनावट का पैदा होता है। मौजूदा बनावट को आप देखें। अमरीका और ब्रिटेन कैपिटलिस्ट देश हैं। वहां की सरकार ने देखा कि जैसे-जैसे देशों को आजादी मिलती जायेगी उनको दिक्तों का सामना करना पड़ेगा और जितना भी रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा वह प्राइवेट कैपिटल के जरिए होना चाहिए। जितनी भी यह संस्थायें बनाई गयीं, इन सब में जो बीमारी है वह शुरू से ही है। वोटिंग की ही बात को आप देखें। नम्बर आफ वोट्स को आप देखें ? शेयर होल्डिंग को आप देखें। वर्ल्ड बैंक का भारत भी एक मैम्बर है। हर देश के 250 वोट हैं।

Plus one additional vote for one lakh dollars of capital subscribed by it.

अब आप देखें कि जो विकसित देश हैं वे ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और उनके वोट ज्यादा हो जायेंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल डिवेलेपमेंट एसोसिएशन में हर एक मैम्बर के पांच सौ वोट हैं

Plus one vote for each 5000 dollars' initial subscription.

अब इसका क्या नतीजा होता है । इंटरनेशनल मानेटरी फंड की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बतलाता हूं। टोटल नम्बर आफ वोट्स जो वर्ल्ड बैंक में हैं वे 2,57,417 हैं। उन में से अमरीका के 63,750 हैं, यू० के० के 26,250 और फ्रांस के 10,750 हैं। उनके कुल 1,00,750

[श्री शिव चंद्र झा]

वोट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पचास परसेंट के करीब वोट वे कंट्रोल करते हैं। तीन चौथाई वोट वे देश कंट्रोल करते हैं जो डिवेलेप्ड देश हैं। उस हिसाब से यह संस्था चलती है। इस वास्ते बुनियादी गलती जो है वह बनावट में है। जो अविकसित देश हैं, जो अंडर डिवेलेप्ड देश हैं, उनको इन संस्थाओं से लाभ तभी हो सकता है जबकि इन संस्थाओं की बनावट में परिवर्तन आए।

रिजर्व बैंक के गवर्नर हाल ही में अमरीका गए थे। मंत्री महोदय भी गए थे। गवर्नर ने वहां एक आवाज उठाई थी। उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। **इकोनोमिक टाइम्ज** अक्तूबर का है, उस में से मैं पढ़ रहा हूं :

"The Governor of the Reserve Bank called for reconsideration of the role of the developing countries in the management of the International Monetary Fund and the World Bank."

तीन चौथाई गरीब देश हैं दुनिया में। लेकिन उनकी आवाज़ नहीं के बराबर है इन संस्थाओं में। विश्व संस्थाओं की जो बनावट है, आई० एम० एफ० है, वर्ल्ड बैंक है या दूसरी संस्थायें हैं, वे तब तक हकीकत में गरीब राष्ट्रों का फायदा नहीं कर सकती हैं जब तक कि डिवेलेपिंग नेशंस के रोल पर दुबारा सोच विचार नहीं किया जाता है। वर्ल्ड आर्गेनाइजेशंस ये जो टर्म्ज़ आफ एग्रीमेन्ट हैं, उन में जड़ में ही खराबी है। खराबी बुनियाद से ही शुरू होती है।

आगे चलकर रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं :

"He publicly criticised a system in which developing countries account for four-fifths of the Fund's membership of 112 nations but had a voting strength of only one-fourth."

"He pointed out that when the quotas were first allocated 25 years ago, all the developing countries except these in Latin America were under colonial rule. If they had been independent in 1944, the world community would have been more conscious of the importance of speeding economic development."

1944 में चार्टर बना था, एग्रीमेन्ट हुआ था। विकासशील देश जो हैं वे उस वक्त गुलाम थे। उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि मंडल भी वहां गया था। लेकिन वह यैसमैन की तरह से गया था। उस वक्त भारत गुलाम था। वह कुछ कर नहीं सकता था। हमारे मैम्बर ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। जिस रूप में उस वक्त यह चार्टर बना था, उसी रूप में यह चला आ रहा है। इसमें अविकसित देशों का या डिवेलेपिंग नेशंस का दोष नहीं है। दोष साम्राज्यवादी ताकतों का है। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के मुल्कों को कलोनियलिज्म में रखा, इम्पीरियलिज्म के मातहत रखा। हकीकत में दोष उनका है। आज समय का तकाजा है, कि बराबरी की भावना वहां पैदा हो। जो अविकसित देश हैं उनको ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा कर्ज़ और सस्ते रेट पर कर्ज़ मिले, लांग रेंज के लिए मिले। वर्ल्ड बाडी में बराबरी की भावना आए। अभी जो बनावट है, उस में बराबरी की भावना नहीं है। इसीलिए गवर्नर ने इस बात को उठाया है।

अब मैं सवाल करता हूं। क्या यह सही नहीं है कि शुरू से ले कर जो डिवेलेप्ड नेशंस हैं, उनको ही इन बाडीज़ से ज्यादा फायदा मिला है बनिस्पत डिवेलेपिंग नेशंस के? आई० एम० एफ०, वर्ल्ड बैंक, आई० डी० ए० इत्यादि जितनी संस्थाएं हैं और जो उनकी बनावट है, उस में क्या उनको ज्यादा फायदा मिला है या नहीं मिला है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि कितनी बार भारत ने आज तक आवाज़ उठाई है कि इस ढांचे में परिवर्तन किया जाए। 1944 में हम

आज़ाद नहीं थे। 1947 में हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद कितनी बार भारत ने आवाज़ उठाई कि इस में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है? कितनी बार हमने आवाज़ उठाई कि टर्म्ज़ आफ़ एग्रीमेन्ट में परिवर्तन होना चाहिए, वोटिंग्ज़ पावर्ज़ में परिवर्तन होना चाहिए ताकि जो वर्ल्ड आर्गेनाइज़ेशंज़ हैं, वे मीनिंगफुल बन सकें और दुनिया का विकास कर सकें?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने जो बात उठाई है भारत सरकार इसको कितनी दूर तक परसू करने जा रही है? इसको मनवाने के लिए भारत सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है?

एफ्रो-एशियन जो नेशंज़ हैं, उनको अपने साथ इस मांग में लेने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है? डिवेलेपिंग देश की मैम्बरशिप 4/5 है लेकिन उनकी वोटिंग स्ट्रेंग्थ एक चौथायी ह है। यह बात रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कही है। जब तक यह वोटिंग वाली बात तय नहीं होती है तब तक कोई भी संस्था मतलब वाली संस्था नहीं बन सकती है और गरीब राष्ट्रों का उससे फायदा नहीं हो सकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार एफ्रो-एशियन नेशंन्ज़ के साथ मिल कर इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक बहुत हद तक अमरीकन फिनांस कैपिटल से प्रभावित है और उस ने पिछले साल बैंक रेट साढ़े छ: परसेंट से बढ़ा कर सात परसेंट कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि बैंक रेट के बढ़ जाने से इस देश के डेवेलपमेन्ट को कितना धक्का लगा है।

यह संस्था एक इकानोमिक या फ़िनांशल और मानिटरी आर्गेनाइज़ेशन कहलाती है, लेकिन इसमें पोलिटिकल बातें भी आ जाती हैं। इकानोमिक ऐंड पोलिटिकल वीकली ने इन्टरनेशनल फिनांस कार्पोरेशन के बारे में साफ रूप से कहा है:

"The philosophy of the operation of the law of commercial enterprise means that which is acceptable to the Wall Street."

वाल स्ट्रीट अमरीकी पूंजीवाद का अड्डा और गढ़ है और उस की इच्छा के मुताबिक ही इस संस्था का दर्शन या फ़िलासिफी बनती है। इस कारण कुछ पोलिटीकल कान्सीक्वेंसिज़ पैदा होते हैं, राजनैतिक दबाव पड़ते हैं, हालांकि इकानोमिक दबाव तो पड़ते ही हैं। क्या यह सही नहीं है कि रुपये के अवमूल्यन के बारे में वर्ल्ड बैंक की तरफ से दबाव डाला गया था और हिन्दुस्तान ने उस दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन किया? क्या यह भी सही नहीं है कि रुपये का दोबारा अवमूल्यन करने के लिए फिर दबाव डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमुक कदम उठाने पर ही भारत को वर्ल्ड बैंक से ज्यादा मदद मिलेगी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इन सवालों के बारे में सफ़ाई दें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री झा, ने ठीक कहा है कि विश्व बैंक के संगठन पर साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। वह प्रभुत्व आज भी है। नव-आज़ाद देशों के संयुक्त राष्ट्र संघ में आ जाने से उस के चरित्र में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो गया है, लेकिन विश्व बैंक का वही पुराना चरित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान चरित्र को देखते हुए क्या सरकार यह आवाज़ उठाने के लिए तैयार है कि विश्व बैंक के लिए प्रतिनिधियों को महाद्वीपों के आधार पर चुनाव के ज़रिए चुना जाये?

श्री झा ने यह भी ठीक कहा है कि विश्व बैंक और साम्राज्यवादी हमारे और

[श्री रामावतार शास्त्री]

अन्य पिछड़े हुए देशों के घरेलू मामलों में दखल देते हैं। इन देशों की सरकारों में साम्राज्यवादी दलाल छिपे रहते हैं, जो उन के इशारे पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने इस देश में रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में देश के हित के विरुद्ध काम किया। वर्ल्ड बैंक ने यह भी राय दी है कि इस देश में चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को अभी लागू नहीं करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में इस तरह के इन्टरफीयरेंस को रोकने के लिए कोई बोल्ड स्टैप लेगी।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : जिस तरह हमारे देश में बिड़ला और टाटा सारे बैंकों के मालिक हैं, उसी तरह वर्ल्ड बैंक के मालिक अमरीका और अंग्रेज हैं। हमारी आबादी अमरीका से तिगुनी है, जब कि बैंक में हमारा रिप्रेज़ेंटेशन अमरीका का आठवां हिस्सा है। यह एक डिसपैरिटी है और इस बड़े देश की तौहीन है। यू० एन० ओ० के जो 112 मेम्बर हैं, उन को वोटिंग राइट और बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार दूसरे बैकवर्ड कन्ट्रीज़ के साथ मिल कर वर्ल्ड बैंक को ज्यादा डैमोक्रेटाइज़ करने के लिए कौन से तरीके अख्त्यार करने जा रही है, ताकि वह वर्ल्ड बाडी ज्यादा इफ़ेक्टिवली हिन्दुस्तान जैसे बैकवर्ड कन्ट्रीज़ की मदद कर सके।

19 hrs

वर्ल्ड बैंक का आबजेक्ट ही यह है कि दुनिया के मुल्कों के देहात और किसानों की बैकवर्डनैस को दूर किया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है कि वर्ल्ड बैंक से ज्यादा रुपया लेकर हिन्दुस्तान के देहात और किसानों की हालत को सुधारा जाये, गांवों का डेवेलपमेंट किया जाए, एग्रीकलचर को बढ़ाया जाये, और रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन वगैरह दूसरे जरूरी कामों को हाथ में लिया जाये। क्या बैंक की तरफ से इस मुल्क को दिये जानेवाली रकम में इज़ाफ़े की कोई उम्मीद है ?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : The notice we have received from the hon. Member is based mainly on three points, with regard to the special drawing rights system allocated for helping the developed nations more than the developing ones, the Reserve Bank Governor's speech there and the actual structural changes in the administration besides the quota arrangements.

But during the course of his observations, he has preferred to cover a much wider arena of discussion and instead of limiting himself to the IMF or the special drawing rights or the 'paper gold' as it is called, he has referred to the World Bank, the IFC and IDA.

As far as IDA is concerned, it is not correct to say that IDA has given credits only for the agricultural sector which in India and Asia is in the private sector. As a matter of fact, as far as India is concerned, we have received from IDA loans for irrigation, industrial raw materials, components, railways, tele-communications and so on and that too not at a high rate of interest as the hon. Member put it, but at 1/4 per cent rate of interest. So whatever information has the hon. Member may have about IDA and its loan-giving policy, I would not at the moment go into details.

As far as SDRs are concerned, this is a sort of improvement in the liquidity position of the countries as such; because the fact remains that while world trade has grown at the rate of 7.5 per cent, the average liquidity of the nations has not increased by more than 2.5 per cent. Therefore, this is an additional reserve created where an equivalent amount of gold is not to be deposited by the member countries and therefore a sort of new reserve or liquid money has been created by opening a new account.

As stated in the answer I gave the other day, in the course of three years about 9.5 billion dollars would be created in this way as this special money.

As far as the drawing of the SDRs is concerned, that would depend upon various quotas that member countries hold. At present, for example, our quota in the IMF is 750 million dollars and in lieu of being the fifth highest quota-holder in the World Bank as well as in the IMF, we happen to be a nominated director there, and to that extent, I would come now to the revision of these quotas in the quinquennial review.

These quotas and SDRs actually give us some rights as well as some obligations. This is only to facilitate a certain ways and means position or reserve position of certain countries. For example, during the drought years when our foreign reserve position was not as good, we needed more finance for reserve purposes and therefore these SDRs to that extent would be helpful to us in such eventualities, and we would be able to draw through this SDR scheme. Those countries which hold larger quotas would in turn be asked to give us their convertible currency. It would be for this international body to decide. For example, when we go in for S.D.R. of 100 million dollars, this body would get convertible currency from Japan, France, Germany, or U.K. or U.S.A., wherever SDRs are there. Therefore, while this gives us the right to draw, at the same time, inputs an obligation on us that to that extent we should be able to provide convertible currency also. As far as convertible currency is concerned, we have not come to that position where we can provide it in a big way. On the contrary, the developing countries would need the drawing rights in their favour more than the other countries having resource to SDR off and on. The fact remains that 80 per cent of the international trade is accounted for by 25 industrially developed countries, and to that extent the position of the developing countries is not a formidable one. That is why from time to time and especially when this quinquennial review is coming where our quota is going to be changed, we are raising certain issues before the International Monetary Fund and the World Bank. One of the issues is that while this review is taking place, the quotas should be given to the developing countries keeping in view the overall position.

Secondly, we have also been advancing the argument that the International Monetary Fund and the World Bank should not give an impression as if it is a rich men's club and therefore the voice of the developing countries should be heard more effectively.

The House knows very well that this quinquennial review of quotas is going to take place on the basis of world trade, economic position and gross national product of each and every country and it is likely that because of these factors the quotas of Japan, Canada, Italy and a few other countries are likely to increase. Our quota is also likely to increase from 750, but we are not likely to remain a nominated member, a status that we have enjoyed for the last 25 years since the Bretton Woods Conference when the World Bank and other bodies came into existence. But though we may not be a nominated member, the position will not change substantially as we will be in a position to become an elected member. As a nominated member we are not in a position in the I.M.F. and World Bank to represent neighbouring countries who want to be represented through us. This we will be able to do as an elected member.

Along with all other developing countries, we have been taking the stand that the quota revision should not be on the basis of world trade, etc., but other considerations should also weigh and that a special quota increase should be given to developing countries.

Shri Jha, Shri Prakash Vir Shastri and Shri Randhir Singh have raised the question of the structural change and what we are going to do with regard to that. As far as the Board of Directors of the International Monetary Fund and the World Bank are concerned, the U.K., U.S.A., Germany, France and India are nominated Directors and the others are elected Directors. The Latin American countries have a quota of three Directors. But a proposal is before these bodies and before the developing countries especially, wherein the suggestion is, why not do away with the nomination completely and why not we have elected directors altogether. This is the proposal, and whenever this proposal is to come before these bodies for consideration, we as one of the developing countries will certainly like to support this proposal, but it would

[Shri P. C. Sethi]

depend on in what manner and at what time it is going to come. But as far as we are concerned, we would certainly be pleased to have this structural change in this form, that instead of nominated members, the elected members may be there. But it might also throw up many problems which would be for the consideration of both these world bodies, and we as a developing country have certainly taken up this position that the voice of the developing countries should increase.

SHRI TULSHIDAS JADHAV (Baramati): Is there voting power for nominated members?

SHRI P. C. SETHI: It is based on the quota that we have got. As the hon. Member has put it, it is 250 for each and on the basis of the quota that one is holding. For one lakh dollars, one vote, and that would be their voting right, and on that basis, even if our quota is reduced, we can get ourselves elected.

As far as the Governor's speech is concerned, I have nothing to contradict, as the hon. Member has quoted actually from his speech. We would have certainly taken this position, and the Governor has certainly voiced our feelings, and he has stated there that the position in these world bodies should change and the developing countries should have a greater voice. There is nothing more that I have to add.

श्री शिव चन्द्र झा : डी-वैल्यूएशन रुपये का किया था तो डिवैल्यूएशन में प्रेशर डाला था तो क्या उस तरह के प्रेशर आज भी डाले जा रहे हैं ?

SHRI P. C. SETHI: I would not enter into that controversy of devaluation. This is one of the very well-conducted debates when it came up in the House. But whatever the other bodies or persons might advise us or may not advise us, the fact remains that whatever the decision we take is our decision and it is not forced upon us by anybody. Therefore, I would not enter into that controversy of devaluation which was very well debated when it came up in the House. Therefore, to that extent, I have nothing more to say.

As far as these world bodies are concerned, and especially these special drawing rights are concerned, this is only to improve the liquidity position, and certainly the SDR depends upon the quota holding, and in regard to it, I have said what is the position and what stand we have taken before these world bodies.

---

19 12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 16, 1969/Agrahayana 25, 1891 (Saka).

40LSS/69—GIPF.